

## प्रीलिमिंस फैक्ट्स : 31 मार्च, 2018

### स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटरनशिप

स्वच्छ भारत अभियान के आयोजक और समन्वयक पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मलिकर 'स्वच्छ भारत समर इंटरनशिप (SBSI), 2018' की पहल की है, जिसका उद्देश्य गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कॉलेज के युवाओं को गाँवों में स्वच्छता से जुड़े कार्यों से जोड़ना है।

- यह प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को किये गए आह्वान के अनुरूप है।
- एसबीएसआई का उद्देश्य देश भर के लाखों शक्ति युवाओं में स्वच्छता क्षेत्र के लिये कौशल वकिसति करना, जन-जागरूकता का प्रसार और स्वच्छ भारत अभियान के लिये जनांदोलन को मजबूती प्रदान करना है।
- इंटरनशिप की शर्तों के अंतर्गत हर अभ्यर्थी को गाँवों और उनके आसपास के इलाकों में श्रमदान, स्वच्छता बुनयादी ढाँचा तैयार करने, व्यवस्था बनाने, व्यवहारगत बदलाव के लिये अभियान और अन्य आईईसी पहलों सहित विभिन्न गतिविधियों पर 100 घंटों तक काम करने की ज़रूरत होगी।
- इंटरनशिप के दशिया-नरिदेशों को उच्च शिक्षा विभाग के साथ परामर्श से तैयार किया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ इंटरनशिप को कॉलेज, महाविद्यालय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाएगी।
- एसबीएसआई को पूरा करने वाले हर इंटरन को स्वच्छ भारत अभियान द्वारा एक इंटरनशिप प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन उच्च शैक्षणिक संस्थानों के वदियार्थियों को चर्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) के अंतर्गत 2 क्रेडिट प्वाइंट्स उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है, जो SBSI को कराएंगे और उसे पूरा करेंगे।

### सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिससे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के तकनीकी सहयोग से महालेखा नयित्त्रक (सीजीए) के कार्यालय द्वारा वकिसति एवं क्रयिान्वति किया गया है।

- पीएफएमएस का मुख्य उद्देश्य एक बेहतर कोष प्रवाह प्रणाली के साथ-साथ भुगतान सह लेखांकन नेटवर्क की स्थापना कर भारत सरकार के लिये एक मजबूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है।
- भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के एक हिस्से के रूप में पीएफएमएस विभिन्न हतिधारकों को वास्तविक समय पर एक विश्वसनीय एवं सार्थक प्रबंधन सूचना प्रणाली और एक कारगर नरिणय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) मुहैया कराती है।
- पीएफएमएस की सबसे बड़ी खासियत देश के बैंकिंग नेटवर्क के साथ इसका एकीकरण करना है। इसके परिणामस्वरूप पीएफएमएस में एक अनोखी कषमता है जिसकी बढौलत वह देश भर में कसिी भी बैंक में खाता रखने वाले लगभग सभी लाभार्थियों/वैडरों को ऑनलाइन भुगतान कर सकता है।
- भारत सरकार के केंद्रीय क्षेत्र की सभी योजनाओं के लिये सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के अनवियार्य (पीएफएमएस) उपयोग से क्रयिान्वयनकारी एजेंसियों तक धनराशिके होने वाले प्रवाह की नगिरानी की जा सकेगी।
- पीएफएमएस के ज़रिये धनराशिके नगिरानी संभव होने से यह पता लगाया जा सकता है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों की क्रयिान्वयनकारी एजेंसियों द्वारा धनराशिके उपयोग की वास्तविक स्थिति क्या है?

### चपिको आंदोलन

26 मार्च, 2018 को Google द्वारा चपिको आंदोलन की 45वीं वर्षगाठ पर इसे अपने डूडल में स्थान दिया गया।

### चपिको आंदोलन क्या है?

- खेजड़ली (जोधपुर) राजस्थान में 1730 के आस-पास अमृता देवी वशिर्नोई के नेतृत्व में लोगों ने राजा के आदेश के विपरीत पेड़ों से चपिककर उनको बचाने के लिये आंदोलन चलाया था। इसी आंदोलन ने आज़ादी के बाद हुए चपिको आंदोलन को प्रेरित किया, जिसमें चमोली, उत्तराखंड में गौरा देवी सहित कई महिलाओं ने पेड़ों से चपिककर उन्हें कटने से बचाया था।

### 'अप्पिको आंदोलन' की तर्ज़ पर

- दक्षिण भारत में भी चपिको आंदोलन की तर्ज़ पर 1983 में 'अप्पिको आंदोलन' शुरू हुआ। 38 दिनों तक चलने वाले इस आंदोलन में भी उत्तरी

करनाटक के गाँवों में महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर उनकी रक्षा की थी।

- नर्मदा बचाओ आंदोलन और साइलेंट वैली आंदोलन में भी महिलाओं ने सराहनीय भूमिका नभाई है। महिलाओं पर पर्यावरणीय मुद्दों के प्रभावों को नमिनलखिति बट्टियों के माध्यम से समझा जा सकता है-
  - ◆ जनि इलाकों में अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, उन इलाकों में जलावन लकड़ी के लिये महिलाओं को दूर तक भटकना पड़ता है।
  - ◆ वही कई लघु व कृटीर उद्योगों को कचचा माल भी इन्हीं वनों से प्राप्त होता है, जो महिलाओं के रोजगार को भी प्रभावित करता है।
  - ◆ रेगसितानी, पठारी और पहाड़ी प्रदेशों में जहाँ जल की भीषण कमी है, वहाँ महिलाओं को जल की व्यवस्था करने के लिये कई किलोमीटर पैदल चलना होता है इत्यादि।

## राष्ट्रीय उच्चतर शक्तिषा अभियान

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रमंडलीय समिति ने मानव संसाधन मंत्रालय के 'राष्ट्रीय उच्चतर शक्तिषा अभियान' (RUSA) को 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने को मंजूरी दी है।

## परमुख बट्टि

- राष्ट्रीय उच्चतर शक्तिषा अभियान (रूसा) एक केंद्रीय प्रायोजति योजना है जिसे राज्यों की पात्र उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वतितपोषति करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में प्रारंभ कया गया था।
- सभी उपघटकों के लिये सार्वजनिक वतितपोषति संस्थानों में परयोजना खर्च केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा साझा तौर पर वहन कया जाता है।
- यह अनुपात पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, हमिचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिये 90:10, अन्य राज्यों और वधिनमंडल वाले केंद्रशासति प्रदेशों के लिये 60:40 तथा बनिा वधिनमंडल वाले केंद्रशासति प्रदेशों के लिये 100:0 है।
- योजना अपने दूसरे चरण में है। इसका लक्ष्य 70 नए आदर्श डिग्री कॉलेजों और 8 नए व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना करना है। इसके अतरिकित योजना चुने हुए 10 राज्य विश्वविद्यालयों और 70 स्वायत्तशासी कॉलेजों की गुणवत्ता और उत्कृष्टता में बढोतरी करेगा। इस संबंध में 50 विश्वविद्यालयों और 750 कॉलेजों को संरचना समर्थन प्रदान करेगी।
- RUSA, 2020 तक देश के कुल नामांकन अनुपात को तीस प्रतशित तक बढाने के साथ ही राज्य सरकारों द्वारा उच्च शक्तिषा में खर्च में बढोतरी करने के लिये भी प्रयास करेगा।
- अन्य बातों के अलावा यह सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को उच्च शक्तिषा के लिये उचित अवसर प्रदान कर उच्च शक्तिषा में समानता को बढावा देगा।
- इसके तहत महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पछिडा वर्ग तथा दवियांगजनों के समावेश को प्रोत्साहित करेगा।